हरियाणा में बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक

18 हजार ग्रुप डी की नौकरियां देकर 15 हजार संविदा नौकरियां समाप्त करेंगे खट्टर

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

बेशर्मी की इन्तेहा किसे कहते हैं ये हरियाणा के नाकारा सिद्ध मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से बेहतर शायद ही कोई बता सके। अपने चार साल के अब तक के कार्यकाल में बमुश्किल कोई रोजगार पैदा कर पाने वाले खट्टर ने 18 हजार डी ग्रुप के पदों के इम्तिहान का मात्र परिणाम घोषित कर देने भर का जश्न 22 जनवरी के राष्ट्रीय अखबारों में पूरे पन्ने पर इश्तेहार देकर मनाया।

यूं तो तीन नारों और मुख्यमंत्री की फुल साइज फोटो वाला इश्तेहार किसी चुटकुले से कम नहीं था। पहला नारा है "प्रतिभा को मिले सम्मान, हरियाणा सरकार का यही पैगाम"। 18 हजार चपरासी और बेलदार स्तर की भर्तियाँ कर किस युवा की प्रतिभा को निखार रहे हैं खट्टर? ज्ञात हो कि इस डी ग्रुप की भर्ती में पीएचडी स्तर तक के अभ्यर्थियों ने शिरकत की थी। अब खट्टर ये बता दें कि क्या चपरासी और पल्लेदार की नौकरी ही वो उचित सम्मान है जिसके लिए कई बच्चों ने कभी उच्च शिक्षा या शोध कार्य को चुना था।

इस 18 हजार की भर्ती के लिए 18 लाख से भी अधिक लोगों ने आवेदन दिया था। जो चयनित हो रहे हैं उनमे अधिकतर मांगी गई शैक्षिक योग्यता से कहीं ज्यादा योग्यता रखते हैं। ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके लिए ये पद निकाले गए, या जो चयनित नहीं हुए? बात यहीं समाप्त नहीं होती। जो भर्तियाँ खट्टर सरकार ने निकाली हैं उस स्थान पर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आधारित 15 हजार से अधिक कर्मी कार्यरत थे। जाहिर है पक्के कर्मी आने पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की छुट्टी होगी ही। तो उन 15 हजार लोगों को क्या कोई अन्य रोजगार उपलब्ध कराया गया? जवाब है नहीं। 18 हजार को लिया और 15 हजार को निकाला, ये है खट्टर का रोजगार माडल। एक हाथ दे कर दूसरे हाथ वापस ले लेना कोई भाजपा सरकारों से सीखे।

इसी के साथ खट्टर की वाहवाही वाले विज्ञापनों में दो अन्य नारे हैं "मेरिट आल्या की बल्ले-बल्ले, भ्रष्टाचारी और दलालों के पड्या ना कुछ पल्ले" एवं "हमारा संकल्प- न पैसा न पर्ची केवल काबिलियत पर भर्ती"। जरा सी छानबीन इन्हें भी खोखला दावा मात्र सिद्ध कर देती है।

फरीदाबाद के 28 वर्षीय जगदीप ने एसआई पुलिस का इम्तिहान दिसम्बर माह में दिया था। उन्होंने बताया कि उनके साथ के कई दोस्तों ने इस डी ग्रुप की नौकरी में जाने के लिए भी धक्के खाये। परीक्षा देकर आये कई मित्रों से बात करने पर पता चला कि उनके नंबर 50 से 60 के बीच में होंगे। कोई भी सूत्र ऐसा नहीं मिला जो बताये कि 70 तक उसके नंबर आ रहे हैं। जगदीप को शक है कि ये परिणाम सच में खट्टर के नारों के अनुरूप हैं।

इम्तिहान होने के बाद सामान्य वर्ग की कटआफ 69 प्रतिशत गई है। इसमें 10 प्रतिशत नंबर आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए हैं। पिछड़ेपन के मूल्यांकन के लिए आयोग ने तय किया था कि यदि किसी के घर का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो वो इस आरक्षण का पात्र नहीं होगा।

हिसार निवासी 22 वर्षीय सोनू एमकॉम के विद्यार्थी हैं। उन्होंने भी इस बार ग्रुप डी की परीक्षा दी थी। सोनू के अनुसार परीक्षा प्रश्न का लेवल अत्यंत कठिन था। या ऐसा कहें कि ग्रुप डी के स्तर अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ये मान कर चल रहे थे मेरिट 50 प्रतिशत के आस-पास ही रहेगी। परन्तु अब जब 69 प्रतिशत की मेरिट गई है तो शक है कि चयन में 'ईमानदार' खट्टर ने ईमानदारी बरती है।

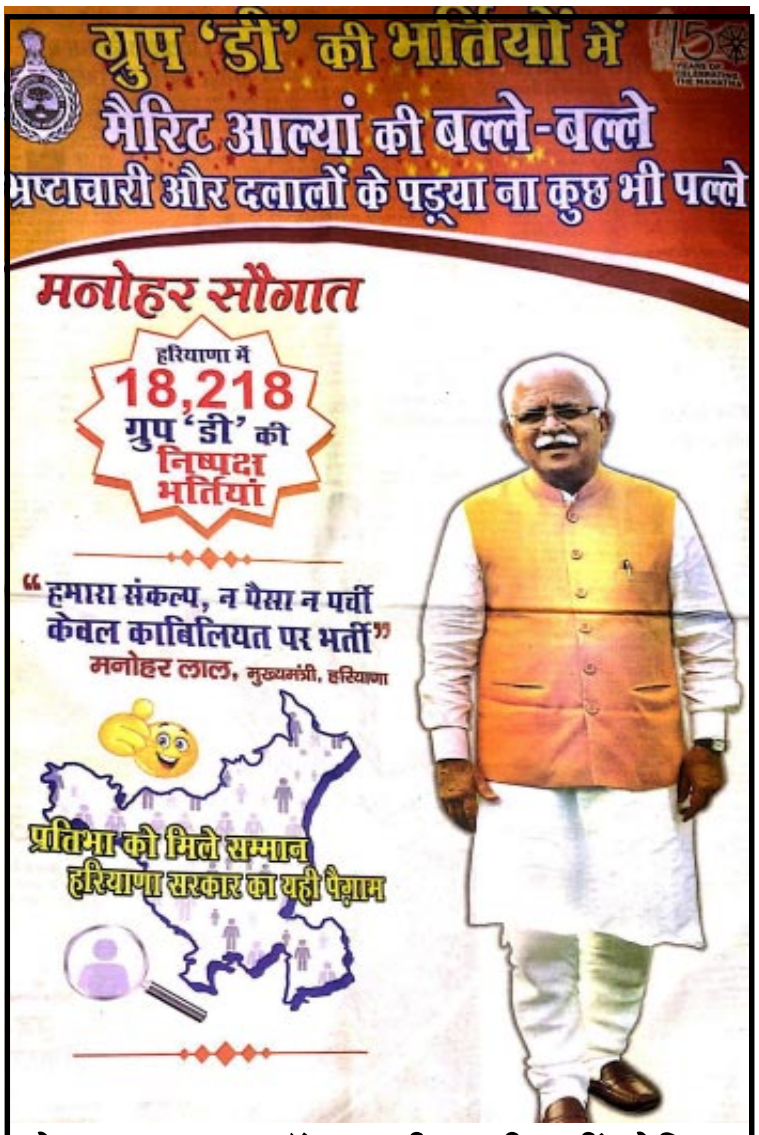

सोनू ने इस बात की आशंका भी जताई कि अफवाहों की मानें तो सरकार ने अंदरखाने अपने लोगों को खुश करने के लिए जल्दी-जल्दी भर्ती का काम संपन्न किया है। वरना क्या कारण है कि जो रिजल्ट चार चरणों में आना तय था उसे आनन-फानन में निकाला गया और अब तुरंत अपनी फोटो के साथ इसका प्रचार भी किया जा रहा है।

30 वर्षीय फरीदाबाद निवासी गुरुदेव ने बताया कि हरियाणा में नायब तहसीलदार का इम्तिहान चार साल से नहीं हुआ जबकि फार्म हर वर्ष भरवाया जा रहा है। एचसीएस का फार्म भी 1000 रुपये ले कर बीते अगस्त में भरवाया जा चुका है। इम्तिहान का पहला चरण अक्तूबर माह में अपेक्षित था जिसकी कोई तिथि आज तक पता नहीं चली है। अब ऐसा लग रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी भर्ती निरस्त हो जाएगी और फिर नए फार्म भरवाये जाएंगे। साफ मतलब है कि आयोग सिर्फ अपनी जेब भर रहा है।

अपने पूरे कार्यकाल में कोई रोजगार न दे पाने के बाद खट्टर के लिए ये जानना बड़ा गौरवशाली होगा कि उनका विधानसभा क्षेत्र करनाल और निवास क्षेत्र रोहतक, प्रदेश भर में बेरोजगारी में अग्रणी हैं। वहीं पूरे हरियाणा में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 5 लाख के करीब पहुँच गई है। हरियाणा में होने वाले अपराधों में संलिप्त ज्यादातर युवक बेरोजगारी के शिकार पाए जा रहे हैं।

शोध को सरकारी तौर पर हतोत्साहित करने का ये नतीजा है कि अब शोधार्थियों की संख्या भी घटने लगी है या उनकी अकादमिक गतिविधि सिर्फ पेपर प्रकाशन तक सीमित हो गई है। जब शोधार्थियों को डिग्री ले कर भी सरकारें चपरासी और बेलदार बना रही हैं तो क्या सिर्फ चौथी तक पढना ही ठीक नहीं होगा? कम से कम उनका वक्त और पैसा तो बचेगा।

सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा लेने वाले आयोग कब आवेदन मांगेंगे और कब भर्ती परीक्षा ली जायेगी इसी के इंतजार में लाखों बच्चे अपना समय गवां देते हैं। और जब तक आयोग और सरकारें आवेदन मांगती हैं कितने ही युवा आयु सीमा लांघ जाते हैं। इम्तिहान और फिर रिजल्ट का इंतजार करने में जिन युवाओं की आयु सीमा पूरी हो जा रही है क्या उनको न्यायसंगत रूप से सरकारें मौका देंगी? अब तक तो ऐसा किसी आयोग ने नहीं किया। सरकार की गलती का खामियाजा युवा अपने भविष्य को कुर्बान कर भुगत रहा है।

क्योंकि इस सड़ते हुए सिस्टम को ठीक करने का जिम्मा किसी सरकार ने नहीं उठाया हुआ है तो उनका मुद्दा हमेशा मंदिर और लव जिहाद ही होगा। यदि इन बच्चों के माता-पिता अपने मूल सवालों में सरकारों से रोजगार के सवाल को दागें तो खट्टर की मजाल नहीं जो 18 हजार चपरासियों के परीक्षा परिणाम पर फोटो छपवाते अपनी।

रोजगार परक मॉडल की कमी नहीं लेकिन सरकारें आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा रहीं

केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के युवाओं को उनका लॉलीपॉप उन्ही को पकड़ा कर बेवकूफ बनाया है। न जाने क्यों युवा भी आरक्षण को रोजगार की गारंटी मानता घूम रहा है जबकि आरक्षण से न रोजगार संभव है न कभी हो सकता है। रोजगार चाहिए तो सबको रोजगार दे पाने वाली व्यवस्था की मांग ही करनी होगी। रोजगार परक विकास के कितने ही माडल इसी भारत देश में मौजूद हैं जिनको देखने की जरूरत सभी सरकारों को है।

पूरब का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघायल में एशिया के सबसे साफ गाँव मावलिंगनाव में पर्यटकों की भरमार है। कारण है इस गाँव की साफ सफाई। देश की सबसे साफ नदी उगानगोत भी इसी गाँव के पास बहती है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि लगता है किसी कांच पर नाव चल रही हो। इसकी सफाई का जिम्मा गाँव वालों ने लिया है और पर्यटकों से इसका शुल्क भी लिया जाता है। गन्दगी फैलाने वालों से 5 हजार जुर्माना वसूला जाता है। ऐसी ही आमदनियों से गाँव के हर व्यक्ति के पास रोजगार है।

महाराष्ट्र के गाँव "हीवरे बाजार" में किसी भी राजनैतिक दल की शाखा नहीं है और न ही कोई होर्डिंग। 315 परिवारों वाले इस गाँव में प्रति व्यक्ति मासिक आय औसतन 32 हजार रुपये है। गाँव वालों ने सूखे से उबरते हुए खुद पौधरोपण की परम्परा शुरू की। पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी गई और नकदी फसलों को भी हतोत्साहित किया गया। भूमिगत जाल के संरक्षण ने गाँव को समृद्ध बनाया। आज गाँव में 350 कुएं और एक तालाब है। प्रशासन की मदद से स्टॉप डैम बने और पशुओं को चारा मिलने लगा। आज इस गाँव में रोज 5 हजार लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। स्कूली छात्र पानी का ऑडिट करते हैं कि कितना पानी बरसा, कितना बहा और कितना जमीन में गया। गाँव से पलायन कर चुके 70 परिवार अब गाँव वापस लौट आये हैं। गाँव में 70 परिवार करोड़पति हैं और हर परिवार से दो सदस्य औसतन उच्च शिक्षा ग्रहण कर उच्च पदों पर आसीन है।

फंडा ये है कि सरकारें युवाओं को सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रही हैं क्योंकि वे अपने मूल सवाल नहीं बदल पा रहे। उपरोक्त माडल ऐसे नमूने हैं जिन्हें अपनाकर गाँव में रोजगार पहुँचाया जा सकता है। शिक्षा और आरक्षण किसी भी समाज को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं दे सकते। खट्टर सरकार तो हर वर्ष गीता जयन्ती मनाने के नाम पर कुरुक्षेत्र में जो सैकड़ों करोड़ का तमाशा करती है उस पैसे से उद्योग लगाकर रोजगार के नए अवसर खड़े किये जा सकते हैं, आज आवश्यकता है इन बहरों को धमाके के साथ झकझोरने की।

मोदी-योगी-खट्टर जैसी झांसा देने वाली तिगडी के भरोसे बैठना युवाओं के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट में जाहिर हुआ है कि भारत की आधी जनसंख्या के पास जितनी सम्पत्ति है उतनी सम्पत्ति सिर्फ भारत के 9 पूँजीपतियों के पास ही है। इतना बड़ा आर्थिक भेद सिर्फ यूँ ही नहीं पैदा हो गया। इस भेद को पैदा किया गया है। पढने वाले छात्रों को चपरासी की नौकरी देकर और गुण्डे मवालियों को एमपी-एमएलए बनने दे कर।

दुनिया के भ्रष्टतम लोगों में शामिल जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति राबर्ट मुगाबे ने एक बात बहुत सत्य कही कि "जब सारी सम्पत्ति पर अपराधियों का ही कब्जा होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे यकीन दिलायेंगे कि पढने-लिखने के क्या और कितने फायदे हैं"। यही हो रहा है हमारे देश में। जो नौकरी और स्थान जिनको मिलना चाहिए वो उससे कम में जीवन जीने को मजबूर हैं और जिनका हक मारा जा रहा है उनको अपराधी बनने के रास्ते धकेला जाना तय है।

रोजगार सिर्फ मोदी की चुनाव घोषणा में

रेलवे ने भी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया। इसके तहत 23 हजार भर्तियाँ की जाएंगी। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1.51 लाख पदों की भर्तियाँ जारी हैं और अगले दो साल में कुल मिलाकर 4 लाख भर्तियाँ की जाएंगी। सोचने वाली बात ये है कि इतने ज्यादा कर्मियों की आवश्यकता रातों रात तो पैदा नहीं हुई होगी। तो ये साढ़े चार साल से मोदी सरकार में बैठे रेल मंत्री सिर्फ ट्वीट करते रहे। इतने सालों से खाली पड़े पद भरे नहीं जा रहे और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो लुभावने वादे की रस्मअदायगी शुरू हो गई।

बहरी और अंधी बनी बैठी सरकारों का ध्यान बेरोजगार युवाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए युवाओं को नए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। इसी तरह के अनूठे प्रयास में राजस्थान अजमेर में स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2015 में रिक्त रह गए 200 से अधिक पदों पर अब नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने शनिवार को आरपीएससी के बाहर सड़क पर मुर्गा बन कर सरकार व आयोग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए।

महाराष्ट्र के मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में कैंटीन वेटर के 13 पदों के लिए 7000 लोगों ने आवेदन किया। यह वैकेंसी चौथी पास लोगों के लिए थी। लेकिन इसके लिए ज्यादातर आवेदन ग्रेजुएशन कर चुके लोगों ने किया। कुछ समय पहले हुई लिखित परीक्षा के बाद 13 लोगों को चुन लिया गया। इनमे 8 पुरुष और बाकी महिलायें हैं। खास बात ये है कि इन चुने हुए लोगों में 12 स्नातक और एक बारहवीं की अर्हता रखता है।

इस बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 और 201। के रिजल्ट जहाँ गलत प्रश्नों के पूछे जाने के कारण आज तक अटके पड़े हैं वहीं 2018 के प्री का रिजल्ट भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। कारण है आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों में 5 को गलत बताना। जबकि अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों पर पहले से सवाल उठाये हुए हैं। ऐसी गलतियां बार-बार किये जाने को गलती माना जाए या आदत, जो केवल और केवल आयोग की जेबें भरने का साधन मात्र बन गया है।

देश में 40 हजार कालेज हैं। औसतन हर कॉलेज से सिर्फ 8 स्तरीय शोध प्रकाशित हो पाते हैं। बीते 5 साल में वैश्विक स्तर पर शोध प्रकाशित होने की संख्या में भारत का योगदान महज 4त्न है। देश में होने वाली रिसर्च का सिर्फ एक तिहाई स्तरीय शोध देश के 97 प्रतिशत कालेजों में हुआ है।

वहीँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाईजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दो दशक में चीन भारत से 28 गुणा ज्यादा पेटेंट भी ले रहा है और पांच गुणा ज्यादा रिसर्चर भी पैदा कर रहा है। चीन अपनी शिक्षा पर जीडीपी का 4 प्रतिशत (40 लाख करोड़) और रिसर्च पर 2.1 प्रतिशत खर्च कर रहा है तो भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 2.5 प्रतिशत (4 लाख करोड़) और शोध पर मात्र 0.7 प्रतिशत खर्च कर रहा है।

जो शोध कर चुके हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं या चपरासी और अन्य नौकरियों में हाथ आजमा रहे हैं। तो सरकार भी कह रही है "तुम डाल-डाल तो हम पात-पात"। यानी दो परीक्षा हम रिजल्ट ही नहीं देंगे। भारत सरकार के हालिया आंकड़ों ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में एक करोड़ से जयादा युवक बेरोजगार हो चुके हैं। युवा रोजगार मांग रहे हैं और मोदी जो पांच साल में 10 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आये थे सबको हिमालय और जंगले जाने की सलाह देने लगे हैं अब। मोदी के पास हर समस्या का इलाज है योग करो, बस योग करो।

स्तरहीन योजना और बिना नीयत के दम पर मोदी भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की डींगें हांकते नहीं थक रहे। साइंस कांग्रेस में अपनी भद्द पिटाने के बाद भी अभी हमारे विश्वगुरु के वाहक रुके नहीं हैं। अपने असीम ज्ञान को नाम बदल कर प्रदर्शित करने वाली भाजपा सरकार के केन्द्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नाम बदलकर भारत माता मंत्रालय करने की सिफारिश कर डाली। जबकि भारत माता के लाल बेरोजगार डोल रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06